थापर संस्थान में उद्योग-संस्थान इंटरफेस कार्यक्रम करवाया, कैबिनेट मंत्री मीत हेयर ने की शिरकत

कारोबारियों ने मंत्री के सामने रखीं 6 मांगें, दर्द छलका

बोले- ऐसे कार्यक्रम हों पर रिजल्ट भी निकलना चाहिए

भास्कर न्यूज | पटियाला

राज्य में उद्योगों की समस्याओं के स्थायी समाधान के लिए इंजीनियरिंग एवं प्रौद्योगिकी संस्थान के सहयोग से औद्योगिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रौद्योगिकी कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इसके तहत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से थापर संस्थान में आयोजित उद्योग-संस्थान इंटरफेस कार्यक्रम का आयोजन किया। कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस दौरान कारोबारियों ने भी विचार रखे। सीआईसीयू के प्रधान उपकार सिंह आहूजा ने मंत्री मीत हेयर के सामने 6 मांगें रखीं, जिसमें उन्होंने उपयोग किए कपड़ों को खतरनाक कचरे की बजाय ऊर्जा स्रोत के रूप में उपयोग करने के लिए तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। इसके अलावा पीपीसीबी को संस्थानों और औद्योगिक घरानों के साथ जल संरक्षण, बिजली की बचत आदि पर उद्योग में नई तकनीकों और प्रक्रियाओं को शुरू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने की मांग की। कई बार पीपीसीबी अधिकारी आते हैं 10-10 फाइलें चेक करते हैं, उसके लिए एक एसओपी बनाई जाए। एक ऑडिट चेक शीट होनी चाहिए, स्व-मूल्यांकन को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। डेयरी से प्राप्त गोबर का उपयोग खाद्य के रूप में किया जाएगा। अकादमियों और औद्योगिक संघों के साथ संयुक्त रूप से सरकार को एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम स्थापित करना चाहिए, जहां मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्टार कैटेगरी में सर्टिफिकेशन दिया जा सके। इससे उद्योगों को खुद की मार्केटिंग करने और पंजाब में और अधिक निवेश लाने में भी मदद मिलेगी। इंडस्ट्रियलिस्ट ने कहा कि इस तरह के इंट्रेक्शन प्रोग्राम तो सरकार करवाती है, लेकिन फोटो खिंचा कर चले जाते हैं। लेकिन, रिजल्ट नहीं निकलता है।

मंत्री गुरमीत सिंह मीत हेयर ने पीपीसीबी और टीआईईटी के संयुक्त उद्यम की प्रशंसा की और कहा कि वे राज्य के उद्योगों के सामने आने वाली विभिन्न पर्यावरणीय और तकनीकी बाधाओं पर चर्चा करेंगे और उनका समाधान खोजेंगे। कहा कि पंजाब सरकार राज्य में उद्योग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रही है, लेकिन पर्यावरण की सफाई भी सरकार की मुख्य प्राथमिकता है।

मंत्री मीत हेयर ने उद्योगपतियों की समस्याओं को दर्ज करवाने के लिए वेबसाइट (आई 3) का शुभारंभ करते हुए कहा कि उद्योग और अनुसंधान संस्थानों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए वेबसाइट तैयार की गई है, जहां विशेषज्ञों द्वारा पंजीकृत समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस मौके मंत्री ने विद्यार्थियों द्वारा तैयार बैटरी से चलने वाले वाहन का निरीक्षण किया व पर्यावरण स्वच्छता पर उद्योगों के लिए तैयार की गई प्रस्तुति देखी।

पत्रकारों से बातचीत में मंत्री मीत हेयर ने कहा कि पंजाब की जो इंडस्ट्री है और उसमें जो भी दिक्कतें आ रही हैं, उनका टेक्नोलॉजी द्वारा किस तरह हल किया जा जाएगा। एसवाईएल पर कहा कि पंजाब के लिए पानी देने को नहीं है।इस मौके पर जिला योजना समिति के अध्यक्ष जस्सी सोहियांवाला, नगर सुधार ट्रस्ट के अध्यक्ष मेघचंद सरमाजरा, एसडीएम। पटियाला डॉ. इश्मित विजय सिंह व डॉ. अनूप कुमार भी मौजूद रहे।

थापर संस्थान में आयोजित उद्योग-संस्थान इंटरफेस कार्यक्रम में मौजूद कारोबारी अपनी बात रखते हुए। बैटरी से बनी कार में बैठे कैबिनेट मंत्री मीत हेयर।

एक साल होने को है, अब तक इंडस्ट्रलिस्ट पॉलिसी तक नहीं बनी : टीआर मिश्रा

लुधियाना के कारोबारी टीआर मिश्रा ने कहा कि एक साल बीतने के बाद भी अभी तक इंडस्ट्रलिस्ट पॉलिसी नहीं बन सकी है जबकि पहले एक से दो महीने में बन जाती थी। पॉलिसी न बनने से जो इंडस्ट्री है उनकी सब्सिडी तक नहीं मिल पा रही है। उनके ऊपर बिजली का चार्ज आदि लग रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई की पंजाब सरकार आने वाले दिनों में 10 रुपए यूनिट बिजली कर देगी। हम लोग पिछले दिनों यूपी के सीएम से मिले थे, वहां पर सीएम से हमने 6 रुपए यूनिट बिजली की मांग रखी थी। वह तैयार हैं। कहा कि पंजाब सरकार बाहर जाती है और घूम फिरकर आती है, सब बातें हवा में हैं। एक रुपए की इन्वेस्टमेंट पंजाब में नहीं आनी और पंजाब से बाहर जा रही है। हमारी डाइंग और टैक्सटाइल फैक्ट्रियां जम्मू कश्मीर तक जाने को तैयार हैं, वहां पर मीटिंग भी हो रही है। सूबा सरकार को चाहिए कि यहां कारोबारियों को बेहतर सुविधाएं मुहैया करवाए ताकि उद्योग पलायन न कर सकें।